

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख राधिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

राजरव विभाग

देहरादून : दिनांक : 03 जनवरी, 2007

विषय: गिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड को गिलंगना जल विद्युत परियोजना हेतु तहसील धनसाली के चार ग्राम- देवलंग, गंगेरी पनेली, बीना एवं रगडी में कुल 7.724 है० भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-210/12ए-1 दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के सन्दर्भ में गुझे सह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय गिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड को गिलंगना जल विद्युत परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-154(2) एवं उत्तरांचल (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत तहसील धनसाली के ग्राम- देवलंग, गंगेरी पनेली, बीना एवं रगडी में कुल 7.724 है० भूमि कय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं :-

- 1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- केता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिराकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिराकी राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिराके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिराके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।



4- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संकमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अरांकमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तरांचल मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

7- इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग जल विद्युत परियोजना हेतु किया जायेगा।

8- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

2- तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।

2- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तरांचल शासन।

3- सचिव, श्रम विभाग, उत्तरांचल शासन।

4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

5- मिलंगना हाइड्रो पावर लिमिटेड, वी-37, सेक्टर-1, नोएडा-201301, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव।